



दैनिक

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, रामपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।

Facebook: दैनिक बुद्ध का संदेश

WhatsApp: 8795951917, 9415163471

Twitter: @budhakasandesh

Email: budhakasandeshnews@gmail.com

Website: www.budhakasandesh.com

उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

एक विश्वास....

सम्पादक : राजेश शर्मा

दिल्ली अग्निकांड के बाद सीएम योगी का सख्त आदेश

यूपी के होटलों-इमारतों का होगा विशेष सुरक्षा जांच

लखनऊ। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्तरां में लगी आग, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य के होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की विशेष सुरक्षा जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी विकास प्राधिकरणों, पुलिस विभागों, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और अग्निशमन विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ कई अन्य विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी ऊंची



इमारतों, कार्यालयों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया जाए और वहां अग्नि सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हों। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि सभी होटलों की विशेष सुरक्षा जांच की जाए और ऑडिट रिपोर्ट

प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर टिप्पणी करते हुए, मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मिश्र ने पुष्टि की कि विशेष टीमों स्थानीय होटलों का सक्रिय रूप से निरीक्षण कर रही हैं और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मिश्र ने एएनआई को बताया सभी होटलों और विभिन्न स्टेशनों में अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी स्टेशन

प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले होटलों का निरीक्षण कर रहे हैं... यदि लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, दिल्ली त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए, उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने घोषणा की कि जिला मजिस्ट्रेटों और स्थानीय अधिकारियों को सुरक्षा अनुपालन को सख्ती से लागू करने के लिए नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए खन्ना ने कहा कि दिल्ली में हुई घटना बेहद दुखद है।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीएफपीडीएस -2026) जारी किया - इससे तहत 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक मूल्य की राजस्व संबंधी खरीद के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएगी। एक पोस्ट में रक्षा मंत्री ने लिखा कि मैं रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों को नई वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीएफपीडीएस -2026) के तहत

12 लाख करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक मूल्य की राजस्व संबंधी



खरीद के लिए बड़ी हुई वित्तीय शक्तियां प्राप्त करने पर बधाई देता हूं। सुधारों के रणनीतिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए रक्षा

मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नया ढांचा फील्ड कमांडरों को तेजी से निर्णय लेने, परिचालन तत्परता बढ़ाने और घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देकर विदेशी उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो फील्ड कमांडरों को और अधिक सशक्त बनाएगी, जिससे त्वरित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी और

अंततः परिचालन तत्परता में वृद्धि होगी। नए दस्तावेज का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है और विदेशी उत्पाद निर्माताओं पर निर्भरता को कम करना है। नीति के आर्थिक लाभों पर जोर देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ढांचा निजी स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों को शामिल करके घरेलू आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, जबकि निर्माण परियोजनाओं के लिए वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने से बुनियादी ढांचे का विकास बहुत तेजी से होगा।

तेल का बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रह सकता है वेनेजुएला

लॉन्ग-टर्म क्रूड डील पर पीएम मोदी ने की वहां के राष्ट्रपति से बात

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया विवाद और रूस से खरीद को लेकर अमेरिका की अस्थिर नीतियों की वजह से भारत कच्चे तेल के एक बड़े आपूर्तिकर्ता की तलाश में है। यह तलाश दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर फिलहाल खत्म होती दिख रही है।

गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्ली रोड्रिगेज के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई है लेकिन इसमें ऊर्जा सहयोग व खास तौर पर कच्चे तेल की खरीद व आपूर्ति का मुद्दा सबसे अहम रहा है। जनवरी, 2026 में अमेरिकी



सरकार ने हस्तक्षेप करके वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन कर रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया और उसके बाद से भारत ने बड़े पैमाने पर उससे तेल की खरीद शुरू कर

दी है। सिर्फ चार महीने पहले भारत वेनेजुएला से एक लीटर भी तेल नहीं खरीदता था और आज यह तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। गुरुवार की बैठक में

किस तरह से क्रूड खरीद के लिए दीर्घकालिक समझौता किया जाए, इस पर बात हुई है। पश्चिम एशिया संघर्ष (28 फरवरी) के बाद से वैश्विक बाजार में ना सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ी हैं बल्कि इनकी आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। अपनी जरूरत का 87 फीसद तक तेल आयात करने वाले देश भारत के लिए समस्या ज्यादा बढ़ी है। भारत 60 फीसद अपना तेल पश्चिम एशियाई देशों से लेता रहा है लेकिन वहां से आपूर्ति बाधित हो रही है। रूस से भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध फिर से लागू होने पर यह मुश्किल हो जाएगा। अभी अमेरिका ने रूस

से तेल खरीद को लेकर भारत को छूट दी है जो 17 जून, 2026 को समाप्त हो रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने देश के संसद में बयान दिया है कि जल्द ही भारत को मिली छूट समाप्त की जाएगी। लिहाजा भारत जल्द से जल्द रूस के एक वैकल्पिक बाजार की तलाश में है। विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि भारत को अपनी जनता व इकोनमी को देखते हुए जहां से जरूरत होगी तेल खरीद करेगा लेकिन इससे इन्कार करना मुश्किल है कि स्थिति बदलने पर रूस से तेल खरीद में कुछ कमी हो।

इर का माहौल बना रहे राहुल गांधी?

आर्थिक सुनामी के दावे पर बीजेपी ने खोला सियासी मोर्चा

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के आर्थिक सुनामी की



आर बढ़ने की चेतावनी देने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, जिसके बाद भाजपा नेता अमित मालवीय ने उन पर भय फैलाने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी सरकार की गांधीजी की आलोचना का जवाब

देते हुए मालवीय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के आर्थिक सुरक्षा उपायों को खत्म करने का दावा करके कांग्रेस नेता भय फैला रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मालवीय ने कई आर्थिक संकेतकों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मई 2026 में ई-वे बिल जनरेशन में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की गतिविधियां मजबूत बनी रहीं, जिनका पीएमआई क्रमशः 56.6 और 58.9 रहा।

भाजपा ने उपायों की सूची जारी की
भाजपा के आईटी सेल प्रमुख ने उन उपायों का भी उल्लेख किया जिन्हें उन्होंने बाहरी आर्थिक दबावों से उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बचाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास बताया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, तो पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती ने उपभोक्ताओं को राहत दी।

नो-फ्लाई जोन बनी अमरनाथ यात्रा

सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर सेवा भी रद्द

श्रीनगर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार दूसरे वर्ष, अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले सभी मार्गों को नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया है और 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिवसीय वार्षिक यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा निलंबित कर दी है। सरकार ने 1 जून, 2026 के आदेश संख्या 321-भंडर के घमाध्यम से अमरनाथ यात्रा के सभी मार्गों को, जिनमें पारंपरिक पहलगाम मार्ग और सबसे छोटा बालताल मार्ग शामिल हैं, 1 जुलाई, 2026



शुनो-फ्लाई जोनर घोषित किया है। तदनुसार, इस वर्ष की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा करने की योजना बना रहे तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा के निलंबन के

बारे में सूचित किया है। अमरनाथ यात्रा के प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएसबी) के एक अधिकारी ने बताया कि तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा मंदिर तक पैदल चलकर या पूरी यात्रा के दौरान पालकी की सहायता से पहुंच सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा कारणों से यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा निलंबित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यात्रा के सभी मार्गों को नो-फ्लाई जोनर घोषित करके सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य यात्रा के दौरान ज़ोन सहित किसी भी प्रकार की अनधिकृत उड़ान गतिविधियों को रोकना है।

नीट पेपर लीक: राहुल गांधी का आरोप, पीएम मोदी की भ्रष्ट व्यवस्था ने लूटा युवाओं का भविष्य

नीट-यूजी परीक्षा के पेपर लीक का लेकर विवाद दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता ने प्रवेश परीक्षा प्रणाली के कथित अनियमितताओं से निपटने के केंद्र के रवैये की आलोचना करते हुए मेडिकल की छात्रा आकांक्षा की मृत्यु का हवाला दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट

करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। एक नीट परीक्षार्थी की मौत का मामला सामने आने के बाद उन्होंने भाजपा सरकार और प्रध. पानमंत्री की जमकर आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी कीमत युवाओं की पूरी पीढ़ी भुगत रही है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि आकांक्षा

डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ६३ लाख का कर्ज लिया। और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहाँ कोचिंग कर सके। उन्होंने आगे लिखा कि एक



पिता ने जो कर सकता था, सब किया। फिर छम्पे पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। उस

अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़ कर चली गई। आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं - मोदी जी की एक भ्रष्ट, टूटी हुई व्यवस्था की देन है। और धर्म प्रधान जी? आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही कमेटी। वही ट्रॉसफर। वही जाँच। न सुधार, न न्याय। मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती - आती-जाती रहती है। लेकिन

आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा (नीट) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 'पेपर लीक के धंधे' में हजारों

टीएमसी में बड़ी बगावत, मेयर का इस्तीफा!

हाल ही में संपन्न हुए राज्य चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाथों करारी हार के कुछ दिनों बाद, तुषमूल कांग्रेस (टीएमसी) पश्चिम बंगाल में सत्ता खोने के बाद अपने विधायी रैंकों में विद्रोह से जूझ रही है। स्पीकर द्वारा 58 बागी टीएमसी विधायकों को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मान्यता देने के बाद, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अब पार्टी को अपने शहरी राजनीतिक ढांचे में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रमुख महापौर पदों पर आसानी वरिष्ठ नेताओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पीकर रथेंद्र नाथ बोस ने विधायक ऋतुब्रता बनर्जी के नेतृत्व में 58 बागी टीएमसी विधायकों को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी। बागी विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया है और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की भूमिका को खुले तौर पर चुनौती दी है।

‘‘प्लास्टिक बेबी’’ को मिला नया जीवन: 10 साल की मेहनत से बहराइच के डॉक्टर ने रचा चमत्कार

दैनिक बुद्ध का संदेश

बहराइच। जिले के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शिशिर अग्रवाल ने एक दुर्लभ बीमारी से जुझ रहे बच्चे को नया जीवन देकर चिकित्सा जगत में मिसाल कायम की है। जन्म के समय प्लास्टिक जैसी झिल्ली में लिपटे इस बच्चे को बचाना लगभग असंभव माना जा रहा था, लेकिन 10 वर्षों की लगातार चिकित्सा, विशेष उपचार और अथक प्रयासों ने उसे सामान्य जीवन की ओर लौटा दिया। मामला चौबेपुरवा भेला गांव का है, जहां अक्टूबर 2016 में तरन्नुम नामक महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो पूरी तरह एक पारदर्शी प्लास्टिक जैसी झिल्ली से ढका

हुआ था। जन्म के बाद बच्चे की हालत बेहद गंभीर थी। वह संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं। ऐसे में परिवार बच्चे को लेकर बहराइच पहुंचे, जहां डॉ. शिशिर अग्रवाल ने इस चुनौतीपूर्ण केस को अपने हाथ में लिया। नवजात को नौ दिनों तक आईसीयू में रखकर गहन निगरानी और उपचार किया गया। बीमारी की गंभीरता को न रो पा रहा था, न सामान्य गतिविधियां कर रहा था। स्थानीय स्तर पर इलाज की

देखते हुए विदेशों तक विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया। बताया जाता है कि इस दुर्लभ बीमारी

पर अमेरिका के चिकित्सकों ने भी अध्ययन किया। इलाज के दौरान दिल्ली और मुंबई से विशेष प्रोटीन तथा एल्युमिन इंजेक्शन मंगवाए गए। वर्षों तक नियमित दवाओं, विशेष देखभाल और फिजियोथेरेपी के माध्यम से बच्चे का उपचार जारी रखा गया। लगभग एक दशक तक चले इस संघर्ष का परिणाम यह रहा कि आज बच्चा करीब 80 प्रतिशत तक स्वस्थ हो चुका है और सामान्य बच्चों की तरह हंसता, बोलता और दैनिक गतिविधियां करता है। चिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार के मामले अत्यंत दुर्लभ होते हैं। लाखों जन्मों में ऐसे बहुत कम बच्चे देखने को मिलते

जिले से दो क्षेत्राधिकारियों का हुआ तबादला

दैनिक बुद्ध का संदेश
बलरामपुर। जिले के दो सीओ का गैर जनपदों में ट्रांसफर किया गया है। बलरामपुर की सीओ ज्योतिश्री को कानपुर भेजा गया है जबकि उतरीला में तैनात रहे सीओ राघवेंद्र सिंह का ट्रांसफर सुल्तानपुर जिले के लिए हो गया है। जिले में दो नये सीओ भेजे गये हैं। कौशाबी जिले में तैनात रहे अभिषेक सिंह व लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात अभय प्रताप सिंह को जिले में तैनाती मिली है। हालांकि 29 मई को जिले से तीन पुलिस इंस्पेक्टरों जिनमें उतरीला के कांतवाल अवधेश कुमार राज भी शामिल हैं उनका स्थानांतरण गैर जनपदों में किया गया था लेकिन उन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है।

संघ शिक्षा वर्ग का आज होगा भव्य समापन, मुख्य अतिथि होंगे अरुण जैन

दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के गोरक्ष प्रांत अंतर्गत सिद्धार्थनगर विभाग द्वारा आयोजित 15 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग (सामान्य) एवं घोष वर्ग का भव्य समापन समारोह शुक्रवार सायं 6 बजे रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, तेतरी बाजार में आयोजित होगा। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन होंगे। वे स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए अपना पाथेय प्रदान करेंगे। पंद्रह दिनों से चल रहे इस प्रशिक्षण वर्ग में स्वयंसेवकों को शारीरिक, बौद्धिक एवं संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया गया। समापन अवसर पर स्वयंसेवक समता, नियुद्ध, शारीरिक विन्यास तथा घोष (बैंड) के विविध कौशलों का सामूहिक प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में गोरक्ष प्रांत के विभिन्न जिलों से स्वयंसेवकों एवं संघ के आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहने की संभावना है। विभाग चालक रामचंद्र चौधरी एवं सर्वाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों, राष्ट्रप्रेमियों एवं आमजन से सपरिवार कार्यक्रम में उपस्थित होकर स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। आयोजकों ने सभी आगंतुकों से कार्यक्रम प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व अपने स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया है।

एंटी करप्शन टीम के हत्ये चढ़े राजस्व निरीक्षक, 10 हजार रुपये रिश्तत लेते गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का संदेश
बस्ती। एंटी करप्शन टीम ने बस्ती जिले के मुंडेरवा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक अशोकलाल को 10 हजार रुपये रिश्तत लेते हुए रंगे हाथ गिरतार कर लिया। गिरतारी के बाद आरोपी को मुंडेरवा थाने लाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के किसान आसमान सिंह ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि उनके पिता के निधन के बाद जमीन के नामांतरण के लिए राजस्व निरीक्षक द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्तत मांगी जा रही है। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। योजना के तहत शिकायतकर्ता को रिश्तत की रकम लेकर भेजा गया। जैसे ही राजस्व निरीक्षक ने 10 हजार रुपये लिए, पहले से तैनात एंटी करप्शन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा—तफरी का माहौल बन गया। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी देवेंद्र अशोकपाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

नेपाल ने सीमा पर सामान लाने की शुल्क सीमा बढ़ाई, 500 नेपाली रुपये तक मिलेगी छूट

दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनौली / महाराजगंज। नेपाल सरकार ने भारत—नेपाल सीमा से आने—जाने वाले यात्रियों के लिए सामान लाने संबंधी नियमों में बदलाव किया है। नए प्राक्धान के तहत अब 100 नेपाली रुपये की जगह 500 नेपाली रुपये तक मूल्य के निजी उपयोग के सामान पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। नेपाल राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, 500 नेपाली रुपये तक की निजी वस्तुओं पर सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, भारत से नेपाल पहुंच रहे यात्रियों के लिए यह राहत सीमित मानी जा रही है, क्योंकि मौजूदा समय में 500 नेपाली रुपये भारतीय मुद्रा में लगभग 312 रुपये के बराबर हैं। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि इस बदलाव से सीमा क्षेत्र के कारोबार पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। सोनौली व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने कहा कि नेपाल सरकार ने केवल शुल्क सीमा बढ़ाने का औपचारिक कदम उठाया है, जबकि वास्तविक राहत के लिए यह सीमा कम से कम 2000 भारतीय रुपये तक होनी चाहिए थी। नए नियम लागू होने के बाद सीमा क्षेत्र के व्यापारियों और यात्रियों की नजर इसके प्रभाव पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित छूट से आम उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, जबकि सीमा पार छोटे व्यापार पर इसका असर पड़ सकता है।

दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिले के लोटन बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आशा बहू, डॉक्टर, जीएनएम और अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना सीएचसी लोटन के समीप संचालित सदभावना हॉस्पिटल एंड प्रैक्चर क्लीनिक की बताई जा रही है। मृतक नवजात के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीडित हरिशंकर मोर्य के अनुसार मंगलवार सुबह गर्भवती रूबी को प्रसव के लिए



बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आरोप है कि रेफर होने के बाद गांव की आशा बहू पुष्पा ने जिला अस्पताल ले जाने के बजाय उन्हें सीधे सदभावना हॉस्पिटल पहुंचा दिया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर नजरूल हसन और जीएनएम पूजा

गोरखपुर में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 253.50 लाख रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की मंजूरी, सीसी सड़क और नाली निर्माण पर होगा फोकस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत गोरखपुर जनपद के लिए 12 विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 253.50 लाख रुपये की धनराशि मंजूरी की है। इस संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश की प्रति जिलाधिकारी गोरखपुर को प्रेषित कर दी गई है।योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न वाडों में सीसी सड़क, आरसीसी नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।स्वीकृत परियोजनाओं में नंदानगर पवन बिहार क्षेत्र में आरसीसी नाली, सीसी सड़क एवं साइड पटरी इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 28.74 लाख रुपये, डॉ. राजेन्द्र नगर में सीसी सड़क एवं नाला निर्माण के लिए 11.35 लाख रुपये, चव्वांदी भवन से ट्रांसफॉर्मर होते हुए मिलन बस्ती की विभिन्न गलियों में सीसी सड़क एवं नाला निर्माण के लिए 40.83 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।इसके अतिरिक्त लोहिया नगर में सीसी सड़क एवं आरसीसी नाली निर्माण हेतु 27.49 लाख रुपये, माधोपुर में 12.31 लाख रुपये, शाहपुर में 6.87 लाख रुपये तथा शक्तिनगर में 23.41 लाख रुपये की धनराशि मंजूरी की गई है।इसी क्रम में सूरजकुंड क्षेत्र में 23.96 लाख रुपये, सेंट झूलेलाल क्षेत्र में 31.89 लाख रुपये, नकहा में 7.25 लाख रुपये, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर में साइड पटरी इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण के लिए 21.46 लाख रुपये तथा इंदिरा नगर में सीसी सड़क एवं आरसीसी नाली निर्माण के लिए 17.94 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से गोरखपुर के विभिन्न वाडों में जल निकासी व्यवस्था सुदृरेगी, सड़क संपर्क बेहतर होगा और नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने से स्थानीय विकास को गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था को राष्ट्रीय पहचान, ‘नेशनल कपेडियम’ में राज्य की तीन अभिनव पहलों को मिला स्थान, डिजिटल सुशासन मॉडल की देशभर में सराहना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गौरवशाली प्रशासनिक इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन तथा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में राज्य का पंचायती राज विभाग ग्रामीण सुशासन और डिजिटल नवाचार की नई पहचान बनकर उभरा है।भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सकलन ‘नेशनल कपेंडियम’ में उत्तर प्रदेश की तीन अभिनव पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इन पहलों को देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में स्थान मिलना राज्य

की तकनीकी प्रगति और ग्रामीण प्रशासन में हुए व्यापक सुधार का प्रमाण माना जा रहा है।पहली प्रमुख पहल के रूप में एआई आधारित पंचायत गेटवे पोर्टल को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से ग्राम सचिवालयों में फेशियल रिकग्निशन और जियो—फेंसिंग तकनीक के जरिए डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रणाली से वित्तीय लेन—देन में पारदर्शिता बढ़ी है और विकास कार्यों में जवाबदेही तय हुई है।दूसरी पहल के तहत ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्रों की स्थापना को राष्ट्रीय मॉडल के रूप में मान्यता मिली है। इससे ग्रामीण नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और

दिव्यांगों को आधार संबंधी सेवाएं गांव स्तर पर ही उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उन्हें शहरों या तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

तीसरी पहल डिजिटल गवर्नंस आधारित वित्तीय प्रणाली से जुड़ी है, जिसके माध्यम से पंचायतों की राजस्व वसूली और बैंक समन्वय की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है। इससे टैक्स संग्रह में पारदर्शिता बढ़ी है और ग्राम पंचायतों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बन रही हैं।इस उपलब्धि पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘डिजिटल

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रसव के दौरान प्रसूता का एक छोटा ऑपरेशन किया गया था, लेकिन बच्चे की मौत के बाद जीएनएम बिना टांका लगाए ही अस्पताल छोड़कर चली गईं। घटना की जानकारी होने पर अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया। सूचना मिलने पर

प्रदेश सरकार के सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण अभियान को लेकर आगरा में व्यापक समीक्षा बैठक, 12 वर्ष पूर्ण होने पर 05 जून से 21 जून तक चलेंगे विविध जनहितकारी कार्यक्रम

लखनऊ। 04 जून, 2026 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री तथा आगरा के प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के विकास, सुशासन, सेवा और जनकल्याण के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली अनेक ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गई हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर जन—जन तक लाभ पहुंचाया गया है।नवीन सॉफ्टवेयर हाउस समागार, आगरा में आयोजित समीक्षा बैठक एवं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 05 जून से 21 जून 2026 तक प्रदेशभर में ‘सेवा, सुशासन, संस्कार एवं सम्मान’ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाई जाएगी।उन्होंने कहा कि संगठन एवं प्रशासन के समन्वित प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों को योजनाओं से जोड़ने तथा उनकी समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएं।अभियान के अंतर्गत 05 जून को विश्व

पर्यावरण दिवस पर “एक पेड़ मां के नाम” के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।08 जून से 14 जून तक जनसंपर्क एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

इसी अवधि में “सरकार आपके द्वार” अभियान के अंतर्गत जनसमस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 जून से 14 जून तक पत्रकार संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रसार किया जाएगा।14 जून से 16 जून तक जनकल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेले आयोजित होंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री

मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे:योगेन्द्र उपाध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने गुरुवार को कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के ‘सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण’ को समर्पित 12 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अवधि भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा की नई पहचान स्थापित करने वाली रही है।उन्होंने बताया कि इस अवसर पर आयोजित किए जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व

मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है और देश आज आर्थिक दृष्टि से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो राष्ट्रीय क्षमता और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है।योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 का हटया जाना, आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक तथा ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम शामिल हैं। इन निर्णयों ने भारत की सुखा नीति को नई मजबूती प्रदान की है।उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के पुनर्जागरण

की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का पुनर्विकास तथा सोमनाथ सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों का संदीर्घकरण वार्षिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है।आर्थिक सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन और नोटबंदी जैसे निर्णयों ने अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और संगठित बनाया है। साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को तकनीकी क्षेत्र मेंअग्रणी बनाया है जिससे डिजिटल भुगतान में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है।उन्होंने

कहा कि पिछले 12 वर्षों में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। नए एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डे और रेलवे नेटवर्क के विस्तार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ते हुए विकास को नई गति दी है।जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, जन-धन योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है और गरीब, किसान, महिला तथा वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है।



डीएलआरसी एवं डीसीसी बैठक में बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा, डीएम ने ऋण वितरण बढ़ाने के लिए निर्देश

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी.एन. की अध्यक्षता में डीएलआरसी एवं डीसीसी बैंकिंग कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों की सीसीएल, फसल बीमा तथा विभिन्न ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के 1800 लक्ष्य के सापेक्ष 491 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें 118 स्वीकृत और 88 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है, जबकि 259 आवेदन लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी

शाखा प्रबंधकों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर तहसीलवार मेगा क्रेडिट कैंप आयोजित कर ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए। डीएम ने स्वयं सहायता समूहों के कम बैंक खाते खोले जाने तथा सीसीएल स्वीकृति की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए एक माह के भीतर लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, पीएम स्वनिधि, ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अन्य योजनाओं के पात्र

लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैठक में जनपद का सीडी रेशियो 43.47 प्रतिशत पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्ययोजना बनाकर इसे बढ़ाने



दबंगों के आगे बेबस बुजुर्ग लेखपाल, शिकायत के बाद भी नहीं हटा खिड़की के रास्ते से अतिक्रमण

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। जनपद के बांसी कोतवाली अंतर्गत ग्राम नरही बुजुर्ग (कुदारन परगना-बांसीपुर) में एक सेवानिवृत्त (रिटायर) लेखपाल और उनके परिवार को गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा प्रताड़ित करने और उनके पुश्तैनी रास्ते को बाधित करने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित बुजुर्ग द्वारा बार-बार जिलाधिकारी और समाधान दिवस में गुहार लगाने के बावजूद अब तक स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई ठोस निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे पीड़ित का परिवार लगातार भय के साए में जीने को मजबूर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम नरही बुजुर्ग निवासी स्वामीनाथ दूबे (पुत्र शोहरत नाथ), जो कि एक अवकाशप्राप्त लेखपाल हैं, उन्होंने जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को दिए शिकायती पत्र (फाइल 1008902111.heic और 1008902112.heic) में आरोप लगाया है कि उनके आवासीय मकान के पीछे महिलाओं के आने-जाने के लिए एक खिड़की और रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते को गांव के ही मनबढ़ किस्म के व्यक्ति ईनल और

मदनेश (पुत्रगण पहेदेव) द्वारा जबरन अपनी गाड़ी खड़ी करके और बाउंड्री (दीवार) खड़ी करने की धमकी देकर अवरुद्ध कर दिया गया है। नायब तहसीलदार की जांच में रास्ता हुआ था सिद्ध



उन्होंने इस संबंध में पूर्व में भी 30 अक्टूबर 2025 और उसके बाद 7 मार्च 2026 को समाधान दिवस में जिलाधिकारी महोदय को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या से अवगत कराया था। आरोप है कि उच्च अधिकारियों से शिकायत करने से खुन्नस खाकर विपक्षी ईनल और मदनेश अब बुजुर्ग व उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि विपक्षी काफी रसूखदार और आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिसके बल पर वे तहसील बांसी और स्थानीय थाने के कर्मचारियों को गुमराह कर मामले का निस्तारण नहीं होने दे रहे हैं। बुजुर्ग स्वामीनाथ दूबे ने जिलाधिकारी से पुनः लिखित अनुरोध करते हुए मांग की है कि महिलाओं के आने-जाने वाले इस खिड़की मार्ग को पूरी तरह साफ और चालू (रंवा) कराया जाए। साथ ही, विपक्षियों से अपने जान-माल का खतरा जताते हुए स्थानीय कोतवाली बांसी व संबंधित तहसील प्रशासन को सख्त निर्देश देने की कृपा की जाए, ताकि मामले का निष्पक्ष निस्तारण हो सके और एक रिटायर्ड कर्मचारी को बुढ़ापे में न्याय मिल सके।

पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीएम और एसपी ने अधिकारियों को किया ब्रीफ

दैनिक बुद्ध का संदेश



सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आक्षेपी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा-2025 को सफुल एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी. एन. एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने गुरुवार को अंबेडकर सभागार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में परीक्षा को

शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया। जिलाधिकारी ने शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय

के साथ परीक्षा संपन्न कराने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ने पीपीटी के माध्यम से परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी गण, क्षेत्राधिकारी सहित पुलिस एवं प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

भाजपा नौगढ़ देहात मंडल कार्यशाला में संगठन मजबूती पर जोर

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। भारतीय जनता पार्टी के नौगढ़ देहात मंडल की कार्यशाला का आयोजन लार्ड बुद्ध पब्लिक स्कूल, शिवपति नगर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सोनू गुप्ता ने की। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल प्रभारी एवं जिला मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान संगठन की आगामी गतिविधियों योजनाओं और कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सदर प्रतिनिधि राजेश मिश्रा, प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष गंगा मिश्रा, राधे बाबा, अजय गुप्ता, अनिल चौधरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यशाला का समापन संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ।



राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 6248 लक्ष्य के सापेक्ष 5998 प्रस्ताव बैंकों को भेजे गए, जिनमें 5776 समूहों को सीसीएल स्वीकृत हो चुका है जबकि 222 मामले लंबित हैं। मुख्यमंत्री युवा

वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025-26 में 55,140 किसानों का बीमा किया गया, जिसमें 9,960 किसानों को 3.47 करोड़ रुपये का दावा भुगतान मिला है। डीएम ने फसल बीमा के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। बैठक में सांसद प्रतिनिधि एस. पी. अग्रवाल, डीसी एन आर एल एम देवनंदन दूबे, लीड बैंक अधिकारी आर.के.

वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025-26 में 55,140 किसानों का बीमा किया गया, जिसमें 9,960 किसानों को 3.47 करोड़ रुपये का दावा भुगतान मिला है। डीएम ने फसल बीमा के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। बैठक में सांसद प्रतिनिधि एस. पी. अग्रवाल, डीसी एन आर एल एम देवनंदन दूबे, लीड बैंक अधिकारी आर.के.

विवाहित महिला की संदिग्ध मौत में मामले में पति गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में विवाहित महिला की संदिग्ध

कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामले में मृतका के मायके पक्ष ने पति, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद एवं क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। उपनिरीक्षक परमानंद राय व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर परसा रेलवे क्रॉसिंग के पास से आरोपी पति दिनेश यादव उर्फ

कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामले में मृतका के मायके पक्ष ने पति, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद एवं क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। उपनिरीक्षक परमानंद राय व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर परसा रेलवे क्रॉसिंग के पास से आरोपी पति दिनेश यादव उर्फ

परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी पति को घटना के 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, पड़रिया निवासी 24 वर्षीय खुशबू का शव मंगलवार को घर के अंदर फंदे से लटका मिला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को

सास और दो ननदों पर दहेज उत्पीड़न एवं हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, जिसके आधार पर थाना शोहरतगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, मृतका की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व पड़रिया निवासी दिनेश यादव उर्फ बुडाऊ से हुई थी। विवाह के बाद उसके एकस पुत्र का जन्म हुआ। मृतका का मायका बलरामपुर जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन

बुडाऊ (27) पुत्र मन्नु यादव निवासी पड़रिया, थाना शोहरतगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मु.अ.सं. 97/2026 में धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया है। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक परमानंद राय एवं हेड कांस्टेबल मनोज प्रसाद शामिल रहे।

गरीब, किसान और महिला कल्याण योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचाएं कार्यकर्ता : फूलचंद जायसवाल

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शोहरतगढ़ मंडल की कामकाजी मासिक बैठक गुरुवार को नगर पंचायत शोहरतगढ़ स्थित श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाना, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा जनसंपर्क अभियान को गति देना रहा। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शिवशक्ति शर्मा ने की, जबकि संचालन मंडल महामंत्री अभिषेक चौधरी ने किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री एवं मंडल प्रभारी फूलचंद जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि फूलचंद जायसवाल ने



कार्यकर्ताओं से संगठन की नीतियों कार्यकर्ताओं से गरीब कल्याण, शक्ति इसके समर्पित जमीनी समासद रविंद्र कुमार वर्मा, जिला क

और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए बूथ स्तर की समितियों को और अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया। साथ ही केंद्र सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर

किसान हित और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शिवशक्ति शर्मा ने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसकी वास्तविक

खेसरहा थाना क्षेत्र के मैथवलिया में मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को किया जागरूक, साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

दैनिक बुद्ध का संदेश

खेसरहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में संचालित मिशन शक्ति फेज-5 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत थाना खेसरहा पुलिस द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम ने थाना क्षेत्र के ग्राम मैथवलिया में बहू-बेटी सम्मेलन एवं साइबर जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को महिला अपराध, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, साइबर ठगी तथा अन्य अपराधों से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने महिलाओं को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन ठगी से बचाव तथा डिजिटल सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनी गई तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार की घटना होने पर बिना संकोच पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित एवं जागरूक बनाना है।

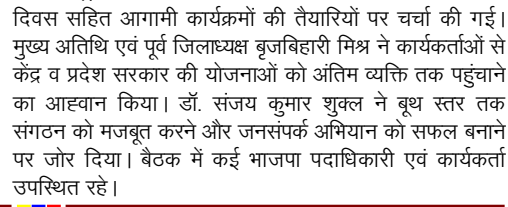
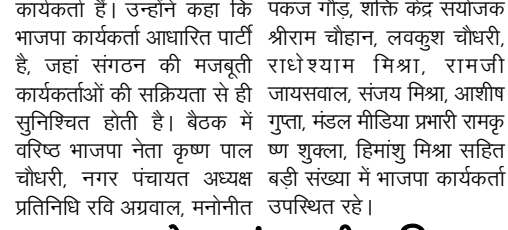


कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि पंकज गौड़, शक्ति केंद्र संयोजक भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी श्रीराम चौहान, लवकुश चौधरी, है, जहां संगठन की मजबूती राधेश्याम मिश्रा, रामजी कार्यकर्ताओं की सक्रियता से ही जायसवाल, संजय मिश्रा, आशीष सुनिश्चित होती है। बैठक में गुप्ता, मंडल मीडिया प्रभारी रामकृष्ण शुकला, हिमांशु मिश्रा सहित चौधरी, नागर पंचायत अध्यक्ष बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, मनोनीत उपस्थित रहे।

भाजपा लोटन मंडल की मासिक बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर मंथन

दैनिक बुद्ध का संदेश

लोटन/सिद्धार्थनगर। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय, लोटन में भाजपा लोटन मंडल की मासिक बैठक मंडल अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जन कल्याण शिविर, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सहित आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि एवं पूर्व जिलाध्यक्ष बृजबिहारी मिश्र ने कार्यकर्ताओं से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। डॉ. संजय कुमार शुक्ल ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया। बैठक में कई भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



सम्पादकीय

क्यों किसी भी विभाग ने निरीक्षण व कार्रवाई की जहमत नहीं उठायी ? क्या निरीक्षण करने वाले अधिकारी ले-देकर स्वामोश होकर बैठ गए ? विडंबना देखिए कि बेसमेंट में कमरे, किचन बना दिए गए, लेकिन वेंटिलेशन व इमरजेंसी एग्जिट का कोई प्रावधान नहीं था । जिससे होटल धुंआ निकासी की चिमनी बनकर रह गया और तमाम लोगों की दम घुटने से मौत हो गई । बताते हैं कि ...

दिल्ली में मालवीय नगर स्थित एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद भले ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया हो, लेकिन सवाल है कि अग्निकांड में मरे लोगों का जीवन कौन लौटाएगा? आखिर देश की राजधानी में अकसर होने वाले अग्निकांडों का सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? क्या इस अपराधिक लापरवाही की जवाबदेही तय होगी? एक बार फिर अंधे लालच और आंख मूंदे तंत्र की लापरवाही से बुधवार को एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जतायी जा रही है। घटना ने एक बार फिर होटल, गेस्टहाउस और रेस्तरां संचालन की निगरानी करने वाली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विडंबना देखिए कि मरने वालों में अधिकांश विदेशी लोग भी हैं, जो सस्ता इलाज कराने भारत आए थे। एक ही परिवार के आठ लोगों के अग्निकांड का शिकार होना बेहद दुःखद है। विडंबना देखिए कि जिस एक मंजिला भवन को छह कमरों का गेस्ट हाउस चलाने की अनुमति मिली थी, वहां शासन-प्रशासन की नाक के नीचे एक छह मंजिला होटल बना दिया गया, जिसमें 26 कमरे और रेस्तेरेंट संचालित किया जा रहा था। जिसमें अस्सी से सौ लोगों की मौजूदगी बतायी जा रही है। निश्चित रूप से यह महज आग से जुड़ा हादसा नहीं है बल्कि होटल संचालन से जुड़े नियमों की अनदेखी, निगरानी करने वाले विभागों की लापरवाही और तंत्र की विफलता का परिचायक है। लेकिन गाहें-बगाहें होने वाले अग्निकांडों के बावजूद तंत्र की काहिली बदस्तूर जारी है। जांच के दायरे में घटना के बाद फरार होटल मालिक ही नहीं, बल्कि वे अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको संचालित करने के नियमों का अनुपालन नहीं किया और भवन निर्माण की स्वीकृति व उपयोग की अनुमति दी। यह जानते हुए भी कि होटल में निकासी का मार्ग बेहद संकरा है और अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के बारे में बताते हैं

कि आपातकालीन निकासी के अभाव व सुरक्षा मानकों का पालन न होने से ज्यादा मौतें हुई। धुआ निकलने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण भी ज्यादा लोग दम घुटने से मौत के मुंह में समा गए। आखिर प्रशासन के अधिकारियों ने यह क्यों नहीं देखा कि स्वीकृत क्षमता से चार गुना विस्तार कर लिया गया है। गेस्ट हाउस के निर्माण में तमाम लाइसेंस शर्तों का धोर उल्लंघन हुआ। आपातकालीन निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिये, बदहवासी में ऊपरी मंजिलों से कूदते नजर आए। होटल के बाहर फेंले बिजली के तार और अग्निफाई में हुई व्यापक क्षति बताती है कि विद्युत सुरक्षा मानकों का भी पालन ठीक से नहीं हुआ। जाहिर बात है कि गेस्ट हाउस से होटल बनाने से, उपयोग में हुए बदलाव की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकाय की होती है। यदि वर्षों से यह अवैध रूप से संचालित था, तो जांच व कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि इसकी अग्नि सुरक्षा को लेकर एनओसी जारी की भी गई थी तो उसके बाद निरीक्षण व नियमों का अनुपालन क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया? जाहिर बात है कि लाइसेंस प्राप्त करने वाले होटलों व रेस्टोरेंट की नियमित जांच करके इनके मालिकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। क्यों किसी भी विभाग ने निरीक्षण व कार्रवाई की जहमत नहीं उठायी? क्या निरीक्षण करने वाले अधिकारी ले-देकर खामोश होकर बैठ गए? विडंबना देखिए कि बेसमेंट में कमरे,किचन बना दिए गए, लेकिन वेंटिलेशन व इमरजेंसी एग्जिट का कोई प्रावधान नहीं था। जिससे होटल धुआ निकासी की चिमनी बनकर रह गया और तमाम लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बताते हैं कि आरोपी होटल मालिक आसपास में ही कुछ पार्टनरों के साथ मिलकर तीन होटल संचालित कर रहा था और सब ही जगह आपराधिक लापरवाही नजर आई। मोटे मुनाफे के लिये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन स्थानीय प्रशासन व जवाबदेह विभाग बेपरवाह बने रहे। निश्चय ही यह स्थिति सख्त कार्रवाई के बाद बदलनी चाहिए।

कभी नानीलैंड होती थी बच्चों की समर कैपिटल

मोबाइल स्क्रीन कभी वो खुशबू नहीं दे सकती जो नानी के आंचल से आती थी। जिस पीढ़ी ने नानी की गोद खो दी, उसने बचपन का सबसे मुलायम तकिया खो दिया। नाना बैठे-बैठे आज भी यह सोचता होगा कि उसके घर को नाने का घर क्यों नहीं कहते। एक जमाना था जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां कुल्लू-मनाली, श्रीनगर, स्विट्जरलैंड नहीं, सीधे 'नानीलैंड' में कटती थीं। गर्मियों की छुट्टियों का मतलब ही होता था- नानी का घर और बच्चों के चेहरे पर ऐसा उत्साह, जैसे विदेश यात्रा पर जा रहे हों। नानी के घर जाने पर बच्चे पांच मिनट में ऐसे तैयार हो जाते थे जैसे पुलिस रेड पड़ने वाली हो। नानी का घर उस समय बच्चों का 5 स्टार रिजॉर्ट होता था। वहां का पंखा भी अलग ही हवा देता था। उसकी चर्र-चर्र में भी लोरी होती थी। नानी का घर कोई साधारण घर नहीं होता था। वह बच्चों का संयुक्त राष्ट्र था। वहां मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे, पड़ोस के बच्चे सब मिलकर ऐसा शोर मचाते थे कि लगता था घर में बच्चे नहीं पूरी बारात ठहरी हुई है। बच्चों की धींगामस्ती देखकर तो घर का कुत्ता भी कोने में बैठकर शांति वार्ता की मांग करता था। नानी के घर में नियम कम, प्यार ज्यादा होता था। सुबह देर तक सोओ तो भी कोई डांट नहीं। रोटी छोड़ दो तो नानी खुद हाथ से कौर बनाकर खिलाती थी और रात को कहानी सुनाते-सुनाते खुद सो जाती थी। बच्चे पूरे दिन छत पर, आंगन में, पेड़ों पर, गली में घूमते थे। कभी लूडो, कभी पिछू, कभी कंचे। और शाम को नानी की आवाज कृआजा बेटा, दूध पी ले। नानी बोलती कि एक रोटी और ले ले। बच्चा कहता कृना नानी पेट भर गया। इस पर नानी कहती पेट भर गया होगा पर नानी का मन नहीं भरा। छुट्टियों के बाद नानी के घर से अपने घर पहुंचते तो बात-बात पर सुनना पड़ता- नानी का घर समझ रखा है क्या। आज सब बदल गया। अब बच्चे नानी के घर जाते कम हैं, इंस्टाग्राम रील ज्यादा बनाते हैं। पहले नानी के घर से लौटते समय आंसू निकलते थे। अब बच्चे पूछते हैं- नानी, आपका वाईफाई इतना स्लो क्यों है? सबसे दुख की बात ये है कि अब नानी के घर रिश्ते कम, फोटो ज्यादा बनती हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। वीडियो कॉल पर नानी मुस्कुरा देती है पर मोबाइल स्क्रीन कभी वो खुशबू नहीं दे सकती जो नानी के आंचल से आती थी। जिस पीढ़ी ने नानी की गोद खो दी, उसने बचपन का सबसे मुलायम तकिया खो दिया। नाना बैठे-बैठे आज भी यह सोचता होगा कि उसके घर को नाने का घर क्यों नहीं कहते।

प्रकृति के बदलते मिजाज को लेकर गंभीरता जरूरी

उस हालत में भविष्य में दुनिया की आबादी का पेट भरने के लिए अन्य संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। आने वाले 24 वर्षों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका को इस चुनौती का भीषण सामना करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में सदी के अंत तक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। इसका असर खाद्यान्न, पेयजल और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा। नतीजन आम आदमी ...

पश्चिमी मॉडल पर आधारित विकास योजनाओं से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। कॉर्पोरेट दुनिया के स्वार्थ को बढ़ावा देने के चलते प्रदूषण बढ़ने से ग्लोबल वॉर्मिंग, जलमैत्रीय व जंगलों का विनाश आदि समस्याएँ बढ़ीं। जिनका असर जीवन व स्वास्थ्य पर हुआ। प्रकृति के उतार-चढ़ाव मानवता के लिए चेतावनी हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1928 में ही उत्पादन और खपत के पश्चिमी मॉडल के चलते वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय असंतुलन की चेतावनी देते हुए कहा थाकूँ ईश्वर कभी नहीं चाहता कि भारत कभी पश्चिम की तरह औद्योगिकीकरण अपनाए। साथ ही कहा था कि एक छोटे से द्वीप साम्राज्य (इंग्लैंड) के आर्थिक साम्राज्यवाद ने आज दुनिया को जंजीरों से जकड़ रखा है। यदि तिस करोड़ की आबादी वाले देश ने ऐसा आर्थिक शोषण किया तो पूरी दुनिया टिड्डियों की तरह बेकार हो जाएगी। गांधीजी का मानना था कि देश को आजादी के बाद गरीबी दूर करने और लोगों के सम्मानजनक जीवनयापन की दृष्टि से आर्थिक विकास करना ही होगा। ऐसे में भारत को अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में कहीं अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाना होगा। सुखद है कि आजाद भारत की सरकारों ने गांधी के विचारों को पूरी तरह बिसरा दिया। परिणामस्वरूप, जहाँ मानव जीवन प्रगतिवृद्ध हुआ, वहीं संसाधनों पर कॉर्पोरेट घरानों के

कच्चे से ग्रामीण और आदिवासी समाज बेदखली का शिकार हुआ। साथ ही औद्योगिक परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के कारण प्रदूषण की समस्या



ने भयावह रूप ले लिया। इस तबाही के विरोध में देश में चिपको, नर्मदा और मछुआरों के आंदोलन सामने आए। इसके उपरान्त देश ने पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई और पारिस्थितिक नुकसान रोकने के लिए अनेक कानून बने। लेकिन सत्ता पर काबिज विभिन्न सरकारों ने समाज के व्यापक हित के बजाय निजी कॉर्पोरेट घरानों के हितों को सर्वोपरि मानकर उनके आगे झुकना उचित समझा। कॉर्पोरेट घरानों के निजी स्वार्थ के चलते प्रदूषित शहर, भयावह स्तर तक प्रदूषित वातावरण, मरती जीवनदायी नदियाँ, प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, गिरता भूजल स्तर, खत्म होते जलश्रोत व जंगल, प्रदूषित मिट्टी, बंजर



हती जमीन आदि पर्यावरण विनाश और तबाही के स्पष्ट सबूत हैं। इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके बावजूद यह सिलसिला बरेकटोकें जारी है। वैश्विक स्तर पर देखें तो बीस वर्ष पहले हम सालाना आठ अरब मीट्रिक टन कार्बन वायुमंडल में छोड़ रहे थे, जिसका आंकड़ा बढ़कर आज डेढ़ गुणा से भी अधिक हो गया। इसके कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा जोरों पर है। प्रकृति का मिजाज बदल रहा है, और इसमें जलवायु परिवर्तन ने अहम भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि दुनिया में ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए कोयला, तेल और गैस का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। भारत के संदर्भ में ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए भारत के प्रयास अभी भी नाकाफी हैं। भारत ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की प्रतिशत में 33-35 प्रतिशत तक कमी लाने का ऐलान किया था, लेकिन पेरिस समझौते के मुताबिक डेढ़ डिग्री के लक्ष्य के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है। देश को विभिन्न क्षेत्रों लिए अपने उत्सर्जन लक्ष्य नए सिरे से तय

करने की आवश्यकता है, अन्यथा 2095 तक धरती का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यदि कार्बन उत्सर्जन में कमी न आई तो जल संकट बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, 8 रुवों की बर्फ तेज गति से पिघलेगी, समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। नतीजन, दुनिया के कई देश पानी में डूब सकते हैं। समुद्र किनारे बसे सैकड़ों शहर-महानगर जलमग्न होएंगे, अल्पभूमि 20 लाख से अधिक प्रजातियां सदा-सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। वहीं सदियों से जीवन के आधार रहे खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। विशेष रूप से बी-1, बी-2, बी-5 और बी-8 जैसी विटामिन में कमी आएगी। बीमारियों से बचाने वाले जैव रसायनों में भी कमी आने की संभावना है। यदि पृथ्वी का तापमान और अधिक बढ़ गया तो धरती का एक-चौथाई हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। वहीं 20-30 प्रतिशत हिस्सा सूखे का शिकार होगा। नतीजतन, दुनियाभर में लगभग 150 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे। जंगलों में आग की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होगी। इसका सबसे ज्यादा असर भारत समेत दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण यूरोप, मध्य अमेरिका और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पर पड़ेगा। चौकाने वाली बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पहले बीते चार दशकों में कम हो चुकी उर्वरा शक्ति वाली जमीन की सहेत बिगड़ने की दर अब सी गुणा बढ़ गई है।

भाषा संबंधी प्राथमिकताएं भी राज्यों के अनुसार भिन्न होती हैं। मध्य प्रदेश में अब तक केवल दो-भाषा प्रणाली ही लागू है, जिसका पालन राज्य बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्कूलों द्वारा किया जाता है। अभिभावक इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस साल कोई बदलाव होगा। देश के बाहर सीबीएसई स्कूलों के साथ भी ऐसा ही है। तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा का चयन किया जा सकता है, पर ...

सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भाषाओं के अध्ययन से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवाल उच्चतम न्यायालय के सामने उठे हैं। इनके पछले दक्षिण में हिंदी बनाम विदेशी भाषा के मामले भी हैं। अभिभावकों की व्यावहारिक समस्याएं, विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों और अध्यापकों की संख्या जैसे सवालों का पिटारा भी अब खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयन्ताबा बागची और विपुल एम पेंवेली की पीठ ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं

किया है, पर उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने अलबत्ता यह कहा है कि बोर्ड का तीसरी भाषा को शामिल करने का निर्णय सिद्धांत रूप में 'प्रशंसनीय' हो सकता है, लेकिन इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू करने में कुछ व्यावहारिक प्रश्न उठेंगे। शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के मद्देनजर इस नीति को लागू करने की तार्किक और व्यावहारिक तथ्यात्मक चुनौतियों को लेकर अदालत और अदालत चिंतित है। बहरहाल, न्यायालय 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। उसी समय इस आदेश को लागू किया जा रहा होगा। शैक्षिक-प्रश्न के अलावा यह राजनीतिक प्रश्न भी है। अपनी भाषा-नीति के अनुरूप ही प्रथमिके ने इस कदम का विरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने बिना परामर्श के अधिसूचना

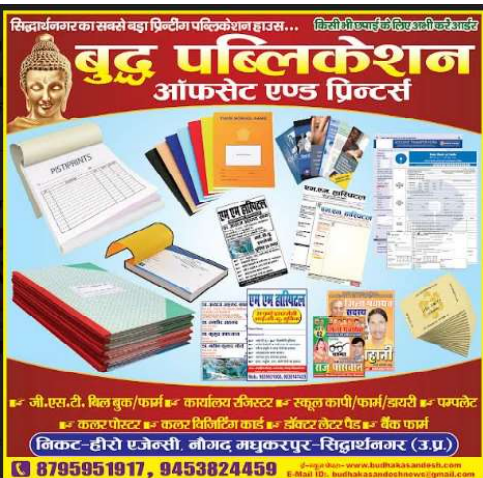


जारी होने की आलोचना की है। दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि सीबीएसई का यह आदेश हिंदी थोपने का प्रयास है। कुछ समय पहले सीबीएसई ने घोषणा की थी कि तीसरी भाषा की अनिवार्यता को 2029-30 शैक्षणिक वर्ष तक स्थगित कर दिया जाएगा। जिस अचानक बदलाव क्यों? एनईपी 2020, जिसके तहत यह आदेश लागू किया जा रहा है, लचीलेपन का वादा करती है। वह गारंटी देती है कि किसी भी छात्र या राज्य पर कोई भाषा थोपी

नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अभिभावक और शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंतित हैं। प्रशिक्षित माता शिक्षकों की कमि और उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धता भी चुनौतियाँ हैं। इस आदेश के विरोधी यह भी कहते हैं कि इससे विदेशी भाषा की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का अहित होगा। कुछ छात्र पहले से ही फ्रेंच, जर्मन या जापानी जैसे विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं वहीं इस नीति के समर्थक कहते हैं कि स्कूली शिक्षा भारतीय भाषाओं से ऊपर विदेशी भाषाओं को रखना न तो तार्किक है और न ही लाभकारी। विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक विषयों के रूप में पढ़ाया जा सकता है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, विदेशी भाषाओं को हतोत्साहित करना नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि यह मुद्दा संघवाद और भाषा के चयन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। भाषा व्यक्तिगत पसंद का विषय है और इसे थोपा नहीं जा सकता। इस पर पीठ ने कहा कि इस तर्क को उलट कर यह कहा जा सकता है कि अधिक भाषाएँ सीखना संघवाद की भावना के लाभ पहुँचाने का काम करेगा। 15 मई को जारी परिपत्र के अनुसार, विदेशी भाषा का चयन करने वाले छात्र दो भारतीय मूल भाषाओं का अध्ययन करने के बाद केवल तीसरी भाषा के रूप में या एक अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में ही ऐसा कर सकेंगे

यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 का हिस्सा है। परिपत्र के अनुसार कक्षा 10 में तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। 'आर3 (तीसरी भाषा)' के सभी मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय-आधारित और आंतरिक होंगे। इसका विवरण सीबीएसई प्रमाणपत्र में परिलक्षित होगा। इस नीति के आलोचक मानते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों ने अपनी-भाषा नीति के प्रति उदासीन रुख अपनाया है, जिनमें से ज्यादातर ने क्षेत्रीय भाषा के बजाय संस्कृत को चुना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पहली भाषा अंग्रेजी, दूसरी हिंदी और तीसरी भाषा संस्कृत है। मध्य प्रदेश में अभी दो-भाषा नीति लागू है, जिसमें अंग्रेजी पहली भाषा और हिंदी दूसरी भाषा है। झारखंड में तीसरी भाषा मुख्य रूप से संस्कृत है, हालांकि कुछ स्कूलों में संथाली जैसी क्षेत्रीय भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ में संस्कृत के साथ-साथ गोंडी जैसी क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जाती है। परेशानी उन अभिभावकों को होती है, जो एक शहर से

दूसरे शहर में जाते हैं और उन्हें अपनी मन-पसंद की विदेशी भाषा पढ़ाने वाला स्कूल नहीं मिलता। मोटे तौर पर बहुसंख्यक गैर-हिंदी राज्यों में बच्चे अंग्रेजी और हिंदी के साथ तीसरी भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा सीखते हैं। राज्यों के बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों में टकराव होता है। यह दिक्कत केवल हिंदी क्षेत्रों में ही नहीं है। दक्षिण में भी है, जहां बच्चों के तीसरी भाषा के रूप में तमिल, कन्नड़ मलयालम या तेलुगु पढ़नी पड़ती है। इससे उन्हें दिक्कत होती है, जो कक्षा पांच से ज़िस्त तीसरी भाषा को पढ़ रहे होते हैं, उसे छोड़ना पड़ता है।



‘कपड़े हो गए छोटे, तो शर्म कहां से आए?’ वाली कॉन्टेंट क्रिएटर दपजं ठपौदवप ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती



सोशल मीडिया पर होने वाली मानसिक प्रताड़ना और श्साइबर बुलिंगश का एक और खौफनाक चेहरा सामने आया है। राजस्थान की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर अनीता बिश्नोई ने बुधवार को कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत जोधपुर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अनीता के परिजनों का आरोप है कि वह पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर हो रही लगातार ट्रोलिंग, भद्दे कमेंट्स और व्यक्तिगत उत्पीड़न के कारण गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही थीं।

राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता के मुद्दों पर वीडियो बनाने के लिए जानी जाने वाली ‘कंटेंट क्रिएटर’ अनीता बिश्नोई को बनार पुलिस थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास पर उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के सदस्यों के अनुसार, बिश्नोई ने कथित तौर पर घर पर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यह घटना बिश्नोई द्वारा सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करने के कुछ घंटों बाद हुई, जिससे उनके सोशल मीडिया फॉलोअर और रिश्तेदारों में चिंता पैदा हो गई।

अपने पोस्ट में, बिश्नोई ने संकेत दिया कि शायद वह फिर कभी दिखाई न दें। बिश्नोई के फेसबुक पर करीब 13 लाख और इंस्टाग्राम पर 6.45 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। उनके पति दिनाराम ने आरोप लगाया कि बिश्नोई को हफ्तों से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और व्यक्तिगत हमलों का सामना करना पड़ रहा था। उनके पति के अनुसार, महिलाओं के पहनावे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उनकी आलोचना और बढ़ गई। साथ ही कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और साथी इन्फ्लुएंसर की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं।

दिनाराम ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप के माध्यम से बिश्नोई को निशाना बना रहे थे, जिससे वह काफी तनाव में थीं। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों के माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे थे। अस्पताल में भर्ती बिश्नोई की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है।

नेटफिलक्स पर रिलीज हुई माँ बहन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की जुगलबंदी ने मचाया धमाल



अगर आप इस वीकेंड के लिए किसी ऐसी मनोरंजक फिल्म की तलाश में हैं जो सरपेंस, कॉमेडी और पारिवारिक ड्रामे से भरपूर हो, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। ध्यान से देखिए़ आज हुआ है एक भयंकर कांड का खुलासा। जैसे धमाकेदार डायलॉग के साथ चर्चा बटोरने वाली नेटपिलक्स की क्राइम-कॉमेडी फिल्म माँ बहन 4 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर दी गई है।

गलतफहमियों, गहरे राजों, इमोशनल उतार-चढ़ावों और पूरे परिवार में मची जबरदस्त अफरा-तफरी से भरी यह फिल्म दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का वादा करती है।

फिल्म माँ बहन नेटपिलक्स पर दोपहर 12:30 बजे रिलीज की जा चुकी है। 2 घंटे 7 मिनट की अवधि वाली यह फिल्म वीकेंड पर पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट डोज है।

इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और मशहूर कंटेंट क्रिएटर धारणा दुर्गा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा फिल्म में रवि किशन, गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह और शार्दूल भारद्वाज जैसे दमदार कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं।

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म के निर्देशक सुरेश त्रिवेणी (जो इससे पहले श्नुम्हारी सुलुश् और श्जलसाश् जैसी फिल्में बना चुके हैं) के अनुसार, टीम एक ऐसी कहानी बनाना चाहती थी जो जमीन से जुड़ी हो और जिसका मनोरंजन स्तर बेहद ऊंचा हो।

एक बिखरा हुआ परिवार: कहानी एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो थोड़ा अजीब और बिखरा हुआ है। इस परिवार की मुखिया मां रेखा (माधुरी दीक्षित) हैं और उनकी दो बेटियां जया (तृप्ति डिमरी) और सुषमा (धारणा दुर्गा) हैं, जो हमेशा बिल्ली-चूहे की तरह आपस में झगड़ती रहती हैं। एक बड़ा कांडश् जिंदगी सामान्य चल रही होती है, जो हमेशा बिल्ली-चूहे की तरह आपस में झगड़ती रहती हैं। एक बड़ा कांडश् जिंदगी सामान्य चल रही होती है, जो हमेशा बिल्ली-चूहे की तरह आपस में झगड़ती रहती हैं।

है कि तभी परिवार में एक बड़ा फ्कांड् (क्राइम्म्हादसा) हो जाता है। इस हादसे के बाद उनकी दुनिया में उथल-पुथल मच जाती है। बदनामी और कानून से बचने के लिए वे अजीबोगरीब और मजेदार हथकंडे अपनाते हैं, जिससे परिस्थितियां और भी ज्यादा उलझती चली जाती हैं।

मुख्य स्टारकास्ट ने अपने किरदारों पर क्या कहा?

पारंपरिक मां की छवि को तोड़ेंगा रेखा का किरदार : माधुरी दीक्षित— फिल्म में मां रेखा का मुख्य किरदार निभा रहीं बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित इस रोल को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा रेखा हिंदी सिनेमा की आम, त्यागी और रोने वाली मां जैसी बिल्कुल नहीं है, और यही बात मुझे इस किरदार में सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। वह शायद एक परफेक्ट मां न हो, लेकिन हर मां की तरह वह अपनी बेटियों का भला चाहती है और इस सारी अफरा-तफरी के बीच अपने परिवार को टूटने से बचाती है। नेटपिलक्स और एबंडशिया एंटरटेनमेंट जैसे पार्टनर्स के साथ काम करना बेहतरीन रहा।

जिम्मेदार बेटी के रोल में हूँ, तृप्ति डिमरी— फिल्म में बड़ी बेटी श्जयाश् का किरदार निभा रहीं तृप्ति डिमरी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जया घर की सुशील और जिम्मेदार बेटी है, जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है लेकिन खुद ही उस दलदल में धंसती जाती है। माधुरी दीक्षित के साथ काम करने पर उन्होंने कहा, म्म्हान माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर् करना, जिन्होंने पूरी एक पीढ़ी को सिनेमा से प्यार करना सिखाया, सचमुच एक जादुई और अविश्वसनीय अनुभव है।

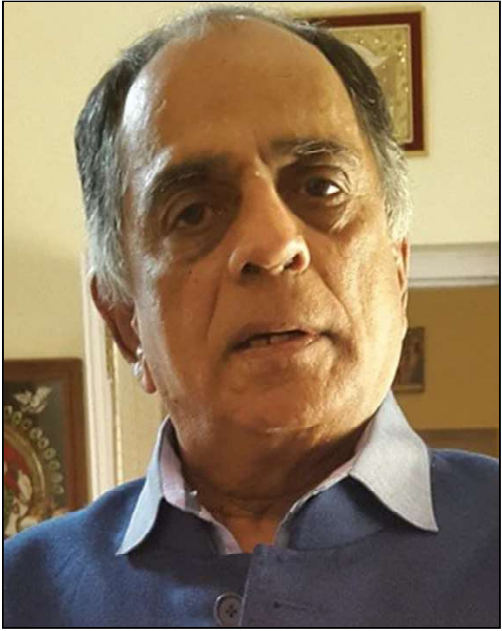
सुषमा के रोल से तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ: धारणा दुर्गा— इस फिल्म से अपना शानदार डिजिटल / स्ट्रीमिंग डेब्यू कर रहीं धारणा दुर्गा ने छोटी बेटी श्शुष्माश् का किरदार निभाया है। धारणा ने बताया, स्क्रिप्ट पढ़ते ही मुझे सुषमा से प्यार हो गया था। फिल्म में तीनों महिलाओं (रेखा, जया और सुषमा) के बीच का जो अपनापन और पागलपन है, वह दर्शकों को बेहद वास्तविक और इंसानी लगेगा।

माधुरी जी के साथ काम करने का सपना पूरा हुआ: रवि किशन— हाल ही में मामला लीगल है सीजन 2 की सफलता का स्वाद चख चुके अभिनेता रवि किशन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, फ्म्हस फिल्म के सेट पर एक अद्भुत ऊर्जा थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि श्म्मां बहनश् की बदौलत मुझे आखिरकार अपने करियर में पहली बार माधुरी जी के साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मिला।

क्यों देखें यह फिल्म?: माँ बहन सिर्फ एक क्राइम-थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के नेतृत्व वाली एक ऐसी डार्क-कॉमेडी है जिसमें रिश्तों की उलझन को बेहद हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। अगर आप माधुरी दीक्षित का एक बिल्कुल नया अवतार, तृप्ति डिमरी की संजीदगी और धारणा दुर्गा का देसी अंदाज देखना चाहते हैं, तो नेटपिलक्स पर माँ बहन को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें।

अलविदा पहलाज निहलानी! 76 वर्ष की उम्र में दिग्गज फिल्म निर्माता का निधन, गोविंदा को दिया था पहला ब्रेक

निहलानी हिंदी सिनेमा के कमर्शियल फिल्म जगत में एक जाना-माना नाम थे। चार दशकों से ज्यादा लंबे अपने करियर में, वे कई मुख्यधारा की फिल्मों से जुड़े रहे, जिनमें हथकड़ी, इल्जाम, शोला और शबनम, श्वाँखेंश्, श्दिल तेरा दीवानाश्, तलाश,



जुली 2 और श्शंगीला राजाश् शामिल हैं।

भारतीय सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अनुभवी फिल्म निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निहलानी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के नानावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड और सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। निहलानी हिंदी सिनेमा के कमर्शियल फिल्म जगत में एक जाना-माना नाम थे। चार दशकों से ज्यादा लंबे अपने करियर में, वे कई मुख्यधारा की फिल्मों से जुड़े रहे, जिनमें हथकड़ी, इल्जाम, शोला और शबनम, श्वाँखेंश्, दिल् तेरा दीवाना, तलाश, जुली 2 और श्शंगीला राजाश् शामिल हैं।

उनकी 1986 की फिल्म श्इल्जामश् से गोविंदा ने डेब्यू किया था, जबकि आग ही आग से चंकी पांडे को पहचान मिली। निहलानी शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेश्, गोविंदा, चंकी पांडे और दिव्या भारती जैसे अभिनेताओं वाली फिल्मों से भी जुड़े रहे। जनवरी 2015 में, निहलानी को **CBFC** का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे अगस्त 2017 तक इस पद पर रहे, जिसके बाद प्रसून जोशी ने उनकी जगह ली।

सर्टिफिकेशन संस्था में उनका कार्यकाल काफी विवादों में रहा। उनके कार्यकाल के दौरान उड़ता पंजाब, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का और इंदु सरकार जैसी कई फिल्मों को सर्टिफिकेशन में देरी, कट लगाने के सुझाव या सार्वजनिक बहस का सामना करना पड़ा।

निहलानी अक्सर सर्टिफिकेशन नियमों और कंटेंट, संस्कृति तथा सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं का हवाला देकर **CBFC** के फैसलों का बचाव करते थे। हालाँकि, उनके कार्यकाल को फिल्म निर्माताओं और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा, जिनका तर्क था कि बोर्ड सर्टिफिकेशन से हटकर सेंसरशिप की ओर बढ़ रहा है।

CBFC में अपने कार्यकाल से पहले, निहलानी कई वर्षों तक श्एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स के अध्यक्ष भी रहे थे।**CBFC** छोड़ने के बाद भी, निहलानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते थे और अक्सर 1980 और 1990 के दशक के अभिनेताओं तथा फिल्म निर्माताओं के साथ अपने काम के बारे में बात करते थे।

मौत का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है आपकी एक आदत, शराब से भी ज्यादा खतरनाक



आजकल खराब लाइफस्टाइल की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, सबसे ज्यादा खतरा दिल की सेहत को होता है। कई आदतें ओवरऑल हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं। ऐसी ही एक आदत है देर तक बैठना। वैज्ञानिकों ने बताया है कि शराब की तरह ही लंबे समय तक बैठना भी सेहत के लिए खतरनाक है। एक अध्ययन में पाया गया कि ड्राइवर और कंडक्टर या गार्ड की सेहत की तुलना की गई, जिसमें पाया गया कि दोनों का खानपान और लाइफस्टाइल काफी हद तक एक जैसी थी, लेकिन ज्यादा देर तक बैठने से हार्ट डिजीज का खतरा, खड़े रहने की तुलना में दोगुना पाया गया है। जानिए लंबे समय तक बैठने के साइड इफेक्ट्स...

बहुत देर तक बैठना क्यों खतरनाक

शोधकर्ताओं ने बताया कि ऑफिस में ज्यादा देर तक बैठने, घर में ज्यादातर देर तक बेड पर आराम करने या ड्राइविंग से सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फिजिकल एक्टिविटीज जितनी ज्यादा कम होती हैं, सेहत के लिए उतनी ही दिक्कतें बढ़ती हैं। ये उम्र को कम करने के साथ ही डिमेंशिया जैसी दिमागी बीमारी और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। इतना ही नहीं हार्ट की समस्याएं भी बढ़ाती हैं।

ज्यादा देर तक बैठने के नुकसान

- जल्दी मौत का खतरा: हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया कि लंबे समय तक बैठे रहने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से समय से पहले मौत का खतरा ज्यादा रहता है। अगर बहुत देर तक बैठते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी इसके खतरे को कम नहीं किया जा सकता है, इस आदत से हार्ट की समस्या, डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियां बढ़ती हैं, जो उम्र को कम करती है।
- डिमेंशिया का रिस्क

शोधकर्ताओं ने बताया कि ऐसे लोग जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उनमें दिमागी समस्याएं यहां तक की डिमेंशिया का खतरा काफी ज्यादा रहता है। ज्यादा देर तक बैठने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा रहता है, जो डिमेंशिया का प्रमुख कारण है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स थोड़ी-थोड़ी देर में उठकर घूमने की सलाह देते हैं।

- मोटापा और हार्ट का जोखिम: अगर ज्यादातर समय बैठकर टीवी देखने, काम करने या ऑफिस में बैठने में बिताते हैं तो बहुत ज्यादा मोटापा और वजन बढ़ सकता है, इससे डायबिटीज से लेकर हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ता है। ज्यादा देर तक बैठे रहने से न सिर्फ कम कैलोरी बर्न होती है, बल्कि शरीर के इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया करने का तरीका भी बदल जाता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण माना जाता है।